



Committed To Excellence

DAILY

CURRENT AFFAIRS ANALYSIS

(Pre+Mains) with MCQ



 | **3 JUNE 2026**




FOR PDF DOWNLOAD
GS WORLD LEARNING APP



Today Important Current Affairs Analysis 3rd June 2026

1. भारत खो रहा है अपने वैज्ञानिक उपकरण बनाने की क्षमता — Mega Science Vision-2035 रिपोर्ट की गंभीर चेतावनी



Committed To Excellence

THE HINDU

Current Affairs Analysis

03 June 2026


The Hindu Page No- 16

India losing ability to build its own instruments: climate science report

Use of imported equipment that remains uncalibrated leads to incorrect data being reported, marring credibility of Indian science: researchers also aim to study long-term impact of uncontrolled tapping of natural resources for renewable energy

Jacob Koshy
NEW DELHI

A group of India's leading climate scientists has warned that the country has almost lost the ability to build its own scientific instruments, leaving its climate observations dependent on imported equipment that is often run uncalibrated for years. This has led to "incorrect data being reported in national and international journals, often leading to questions on the credibility of Indian science", they



Heat is on: The warning lands at a time when India is already facing the harmful effects of the warming climate. SHIV KUMAR PUSHPAKAR

complaints over sub-standard materials. The warning also lands at a time when India is already facing the harmful effects of the warming climate, from intensifying heatwaves and erratic monsoons to accelerating Himalayan glacier melt – the very trends that reliable, well-calibrated observations are meant to track. The MSV exercise, historically used to plan large, long-horizon projects in fields such as nuclear and high-energy physics, was for the first time extended to climate research, ecologists' justification for studying "uncontrolled" renewables is cautious rather than sceptical. The report said that while "renewable energy seems to be the right solution to replace polluting energy sources, studies are needed to understand the long-term consequences of the uncontrolled tapping of natural resources." India has pledged 500 GW of non-fossil capacity by 2030, and crossed the halfway mark on installed electricity capacity from non-fossil sources in 2025.

भारत खो रहा है अपने वैज्ञानिक उपकरण बनाने की क्षमता — Mega Science Vision-2035 रिपोर्ट की गंभीर चेतावनी

IISc बेंगलुरु की अगुवाई में तैयार रिपोर्ट PSA कार्यालय को सौंपी — uncalibrated imported equipment से गलत डेटा, भारतीय विज्ञान की विश्वसनीयता पर सवाल

3 जून, 2026 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | जलवायु विज्ञान

भारत के अग्रणी जलवायु वैज्ञानिकों ने एक गंभीर चेतावनी दी है — देश ने अपने वैज्ञानिक उपकरण स्वयं बनाने की क्षमता लगभग खो दी है। इसके परिणामस्वरूप जलवायु अवलोकन आयातित उपकरणों पर निर्भर हो गया है जो अक्सर वर्षों तक बिना calibration के चलते रहते हैं। यह चेतावनी **Mega Science Vision-2035 (MSV)** रिपोर्ट के जलवायु अनुसंधान खंड में दी गई है।

MSV रिपोर्ट क्या है?

- यह भारतीय जलवायु अनुसंधान समुदाय द्वारा तैयार एक road map है जिसमें **Indian Institute of Science (IISc), बेंगलुरु** नोडल संस्था के रूप में कार्यरत है। इसे भारत सरकार के **Principal Scientific Adviser (PSA)** के कार्यालय — प्रोफेसर Ajay K. Sood की अगुवाई में — को सौंपा गया है।
- MSV exercise ऐतिहासिक रूप से परमाणु और उच्च-ऊर्जा भौतिकी जैसे क्षेत्रों में बड़ी, दीर्घकालिक परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए उपयोग की जाती रही है। पहली बार इसे जलवायु अनुसंधान, पारिस्थितिकी और खगोल विज्ञान तक विस्तारित किया गया है।

प्रमुख चिंताएं

1. वैज्ञानिक उपकरण निर्माण क्षमता का हास

रिपोर्ट में कहा गया है कि uncalibrated imported equipment से "राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में गलत डेटा रिपोर्ट किया जा रहा है जिससे भारतीय विज्ञान की विश्वसनीयता पर अक्सर सवाल उठते हैं।"

- **Atmanirbhar Bharat से विरोधाभास:** यह चेतावनी सरकार की Atmanirbhar नीति के साथ एक असहज स्थिति पैदा करती है। Government e-Marketplace (GeM) portal को सार्वजनिक वैज्ञानिक संस्थानों के लिए अनिवार्य किए जाने से वैज्ञानिकों को customized, उच्च-गुणवत्ता वाले उपकरण प्राप्त करने में कठिनाई हुई। GeM vendors अक्सर इन specifications को पूरा नहीं कर सके। जून 2025 में वित्त मंत्रालय ने sub-standard materials की शिकायतों के बाद कुछ नियमों में ढील दी।

2. नवीकरणीय ऊर्जा के दीर्घकालिक जलवायु प्रभाव

रिपोर्ट ने बड़े सौर और पवन संयंत्रों के जलवायु पर प्रभावों को "poorly understood" बताते हुए प्राकृतिक संसाधनों के "uncontrolled" दोहन के दीर्घकालिक जलवायु परिणामों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वैज्ञानिकों का यह दृष्टिकोण **सतर्कतापूर्ण** है, संशयपूर्ण नहीं — वे नवीकरणीय ऊर्जा के विरोधी नहीं हैं बल्कि इसके वैज्ञानिक अध्ययन की मांग कर रहे हैं।

रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें

- **Carbon की सामाजिक लागत:** CO2 के एक अतिरिक्त टन से होने वाले नुकसान की गणना के लिए वैज्ञानिक तरीके विकसित करना और "polluter pays" सिद्धांत को लागू करने का तंत्र।
- **स्वदेशी Earth System Model:** मौजूदा भारतीय models जो "अमेरिका या यूरोप से अनुकूलित" हैं, उनसे अलग "first principles" से एक indigenous Earth System Model का निर्माण।
- **आठ Mega Projects:** 2035 तक तीन पांच-वर्षीय चरणों में observatories, satellites, in-situ networks, field campaigns, indigenous sensors, carbon-neutrality research और adaptation science को शामिल करते हुए।

महत्व

यह रिपोर्ट कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहला, भारत पहले से ही intensifying heatwaves, erratic monsoons और Himalayan glacier melt जैसे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का सामना कर रहा है — और इन्हीं trends को track करने के लिए reliable, well-calibrated observations की आवश्यकता है। दूसरा, 2030 तक 500 GW non-fossil capacity के लक्ष्य के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन और भी जरूरी हो जाता है। तीसरा, indigenous scientific instrument manufacturing की क्षमता का पुनर्निर्माण Atmanirbhar Bharat के वास्तविक अर्थ में एक अनिवार्य कदम है।

स्रोत: The Hindu | Mega Science Vision-2035 Report | IISc Bengaluru | PSA Office

2. भूमि पूलिंग: भूमि अधिग्रहण की जटिलताओं का समाधान — राजस्थान की नई पहल और देशव्यापी संभावनाएं

How land pooling solves acquisition woes

Rajasthan has recently announced the State's first land pooling scheme. The government is optimistic that the scheme will help with land acquisition and deliver the land needed for roads, infrastructure, and development activities. Other States, too, are either actively thinking of implementing land pooling schemes. While States such as Gujarat and Maharashtra have found success, much will depend on localised innovation and institutional flexibility. Urban infrastructure projects in India have historically relied on land acquisitions. This process has become increasingly complex and



Amit Gotecha
An urban planner advising various State governments on town planning schemes

implemented in Gujarat and Maharashtra, is among the most successful land-pooling models in India. Under this model, landowners voluntarily contribute about 25-40% of their land to provide infrastructure such as roads, parks, public amenities, and housing for economically weaker sections. The remaining land (60-75%) is returned to them as reconstituted plots that are better shaped, serviced, and more valuable. This method integrates land assembly, infrastructure provisions, and cost recovery. A key strength of the TP scheme is its participatory, people-centric approach. It is also financially self-sustaining, as

Development Authority Act, 1985 included provisions for the preparation and implementation of development schemes, it lacked clarity on critical aspects, including the percentages for land appropriation and institutional roles. An equally significant challenge was the absence of digitised land records; land records in Guwahati were maintained manually. Additionally, discrepancies were observed between revenue records and ground conditions. To address this, rather than conducting time-consuming joint measurement surveys, the existing map was retained as is, and final plot allocations were based on the

भूमि पूलिंग: भूमि अधिग्रहण की जटिलताओं का समाधान — राजस्थान की नई पहल और देशव्यापी संभावनाएं

गुजरात और महाराष्ट्र की सफलता से सीख — Town Planning Schemes बन रही हैं शहरी बुनियादी ढांचे की नई उम्मीद

3 जून, 2026 | शासन एवं नीति | शहरी विकास

राजस्थान ने हाल ही में राज्य की पहली भूमि पूलिंग योजना की घोषणा की है। सरकार को उम्मीद है कि यह योजना भूमि अधिग्रहण की समस्याओं को सुलझाने और सड़कों, बुनियादी ढांचे एवं विकास गतिविधियों के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने में मदद करेगी।

भूमि अधिग्रहण की समस्या

- भारत में शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं ऐतिहासिक रूप से भूमि अधिग्रहण पर निर्भर रही हैं। यह प्रक्रिया विशेष रूप से **भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013** के लागू होने के बाद और अधिक जटिल और वित्तीय रूप से बोझिल हो गई है।
- पुनर्वास प्रावधानों से वित्तीय दायित्व बढ़ गए हैं जिससे बड़े पैमाने पर अधिग्रहण तेजी से अव्यवहार्य हो रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप नियोजित बुनियादी ढांचे और उसके कार्यान्वयन के बीच बढ़ता अंतर देखने को मिल रहा है।

भूमि पूलिंग – एक व्यवहार्य विकल्प

- भूमि पूलिंग मॉडल में भूखंड मालिक स्वेच्छा से बुनियादी ढांचा विकास के लिए भूमि का योगदान करते हैं और बदले में serviced land का एक हिस्सा प्राप्त करते हैं। यह विधि अनिवार्य अधिग्रहण की आवश्यकता को कम करती है और विकास के लाभों को सभी हितधारकों में वितरित करती है।

Town Planning (TP) Scheme – भारत का सबसे सफल मॉडल

- गुजरात और महाराष्ट्र में व्यापक रूप से लागू TP Scheme भारत के सबसे सफल भूमि पूलिंग मॉडलों में से एक है।
- इस मॉडल में भूखंड मालिक स्वेच्छा से अपनी **25-40%** भूमि सड़कों, पार्कों, सार्वजनिक सुविधाओं और EWS आवास जैसे बुनियादी ढांचे के लिए योगदान करते हैं। शेष **60-75%** भूमि उन्हें बेहतर आकार, सुविधाओं से युक्त और अधिक मूल्यवान reconstituted plots के रूप में वापस मिलती है।
- **प्रमुख ताकत:** यह participatory और people-centric है। यह financially self-sustaining भी है क्योंकि landowners से incremental charges विकास के दौरान वसूले जाते हैं – अग्रिम नहीं।

राज्यवार अनुभव

- **गुजरात:** भूमि पूलिंग लगभग 100 वर्ष पहले शुरू हुई और Gujarat Town Planning and Urban Development Act, 1976 के तहत औपचारिक रूप दी गई। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा और गांधीनगर में 1,000 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र TP schemes के माध्यम से नियोजित हो चुका है।
- **महाराष्ट्र:** गुजरात के विपरीत महाराष्ट्र TP schemes के लिए अपने statutory provisions को समय पर update करने में विफल रहा। हालांकि पुणे और MMRDA ने हाल ही में शहर के peripheral areas में इस मॉडल को फिर से अपनाया है।
- **गुवाहाटी:** Guwahati Metropolitan Development Authority Act, 1985 में प्रावधान थे लेकिन भूमि appropriation के प्रतिशत और संस्थागत भूमिकाओं पर स्पष्टता का अभाव था। Digitised land records नहीं थे — records manually maintained थे। समाधान के रूप में joint measurement surveys के बजाय existing map को as-is बनाए रखा और final plot allocations revenue records पर आधारित किए। Private landowners से केवल **12-15%** भूमि योगदान मांगा गया जो सामान्य 35-45% से बहुत कम है।
- **राजस्थान:** 2016 से statutory provisions में भूमि पूलिंग को मान्यता थी लेकिन अनुभव का अभाव था। अब land-value calculations में संशोधन किए जा रहे हैं और सरकार ने लागत का एक हिस्सा स्वयं वहन किया है।

आगे की राह


- तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्य जो अब भूमि पूलिंग अपनाने की सोच रहे हैं उनके सामने पहले भूखंड मालिकों को योजना के लाभ समझाने की चुनौती है। भूमि पूलिंग की सफलता तीन कारकों पर निर्भर करेगी — स्पष्ट legislation, समायोजित land-contribution mechanisms और equitable financial models।

महत्व

- भूमि पूलिंग केवल एक वैकल्पिक land assembly mechanism नहीं है — यह शहरी विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को बदलने का प्रयास है। जहां compulsory acquisition displacement और विरोध पैदा करता है, वहीं TP schemes landowners को विकास के भागीदार बनाती हैं।
- गुजरात का 100 साल का अनुभव दर्शाता है कि सही institutional framework और local innovation के साथ यह मॉडल शहरी India के बुनियादी ढांचे की समस्याओं का टिकाऊ समाधान बन सकता है।

स्रोत: The Hindu | शहरी विकास मंत्रालय | Gujarat Town Planning and Urban Development Act, 1976

3. भारत के semiconductor उद्योग का भविष्य: NITI Aayog की Frontier Tech Hub रिपोर्ट — चुनौतियां विकट, लेकिन राष्ट्रीय हित में आगे बढ़ना अनिवार्य



Committed To Excellence

THE HINDU

Current Affairs Analysis

03 June 2026

The Hindu Page No- 11

The future of India's chip industry

A new NITI Aayog report says India's semiconductor ecosystem is not yet equipped to fully meet domestic demand, while stressing the need to strengthen local manufacturing, as geopolitical pressures could potentially disrupt the electronics supply chain

EXPLAINER

Arton Deep

NITI Aayog's Frontier Tech Hub released a report last week that had two main messages: first, that India faces steep challenges in developing world-class semiconductor manufacturing capabilities, and second, that national interest necessitated pursuing this field doggedly regardless of those difficulties.

The Union government has made chipmaking a priority, since semiconductors are a part of nearly all electronics, from consumer gadgets to defence gear. Yet, India does not have a single fabrication unit, with the first expected to open in Dholera, Gujarat by 2028, with a total of ten in various stages of development. Multiple semiconductor packaging and testing facilities have been



investors, the report warns. This translates to a shift away from directing public funds towards frontier chips, whose transistors are the smallest – 3 to 7 nanometres – and towards “mature, advanced” –aligned with strategic relevance– as well as compound nodes,” the report says.

The report is key in understanding the potential scope of ISM 2.0, since its ambition is defined and largely stays out of big-ticket frontier fab projects. It advocates, for instance, “selective depth, capital efficiency and system-level differentiation, rather than attempting to duplicate the full global manufacturing spectrum.”

For instance, packaging, which is among the last steps of a chipmaking process, and less expensive and complex than fabrication, is identified as a “core production pillar, not a downstream activity” in the report. The report calls for “rapid export substitution in high

THE GIST

The Union government has made semiconductor manufacturing a priority, but India does not yet have a fabrication unit. A recent report by NITI Aayog's Frontier Tech Hub underscores the need to bolster local manufacturing.

The report urges the government to work on “building sovereign design and research capabilities, R&D excellence and harnessing agentic AI for semiconductor engineering.”

भारत के semiconductor उद्योग का भविष्य: NITI Aayog की Frontier Tech Hub रिपोर्ट — चुनौतियां विकट, लेकिन राष्ट्रीय हित में आगे बढ़ना अनिवार्य

2028 तक Dholera में पहला fab unit — \$45-60 billion का निवेश जरूरी — China adversary, US-Japan-EU-South Korea priority partners

3 जून, 2026 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | semiconductor नीति

NITI Aayog के Frontier Tech Hub ने 'Future of India's Semiconductor Industry' शीर्षक से एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है जिसके दो मुख्य संदेश हैं — पहला, भारत को विश्व स्तरीय semiconductor विनिर्माण क्षमता विकसित करने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, इन कठिनाइयों के बावजूद राष्ट्रीय हित में इस क्षेत्र में दृढ़ता से आगे बढ़ना अनिवार्य है।

भारत की semiconductor स्थिति — कहां खड़े हैं हम?

- Semiconductors लगभग सभी electronics में होते हैं — consumer gadgets से लेकर defence gear तक। इसके बावजूद भारत में अभी तक एक भी **fabrication unit (fab)** नहीं है। पहला fab **2028 तक गुजरात के धोलेरा** में खुलने की उम्मीद है — कुल मिलाकर दस fabs विकास के विभिन्न चरणों में हैं।
- रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि **"भारत का स्थानीय ecosystem घरेलू semiconductor मांग को पूरी तरह पूरा करने के लिए तैयार नहीं है।"** घरेलू electronics assembly में उपयोग होने वाले chips भी मुख्यतः विदेशों से आते हैं।

India Semiconductor Mission (ISM)

- सरकार ने **₹76,000 करोड़ के corpus** के साथ India Semiconductor Mission की स्थापना की है। यह राशि लगभग पूरी तरह से semiconductor fabs, component manufacturing incentives और छात्रों व academia के लिए industry-grade semiconductor design applications की bulk subscriptions के लिए निर्धारित है।
- सबसे महत्वाकांक्षी fab projects को **50% से अधिक capital subsidies** मिली हैं जबकि अन्य projects को production/output-linked incentives दिए गए हैं।

स्थानीय निर्माण क्यों जरूरी?

रिपोर्ट दो प्रमुख कारण बताती है —

- **भू-राजनीतिक जोखिम:** Taiwan में कोई बड़ी घटना electronics supply chain को भारी रूप से बाधित कर सकती है। India की import-dependence इस जोखिम को और बढ़ाती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** "Defence systems में उपयोग होने वाले कई semiconductor parts भारत के बाहर बनते हैं — जिससे aerospace और defence programmes में बढ़ते राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे पैदा हो रहे हैं।" रिपोर्ट कहती है कि इस क्षेत्र में "एक दशक या उससे अधिक समय तक sustained, mission-mode commitment" की जरूरत है।

प्रमुख चुनौतियां

- **Fab Gestation Period:** Fab units को उत्पादन शुरू करने से पहले आमतौर पर **4-5 वर्ष** लगते हैं। Gestation phase में global players से **50 से अधिक specialized equipment** खरीदने में निवेश करना पड़ता है। उत्पादन के बाद भी yield optimisation और reliability testing में "कई quarters" लगते हैं।
- **Talent Development:** Fabs के लिए आवश्यक skilled manpower विकसित करना भी समय-साध्य है।
- **Sovereign Design Capability:** रिपोर्ट सरकार को "sovereign design और research capabilities, R&D excellence और semiconductor engineering के लिए agentic AI का उपयोग" विकसित करने पर काम करने का आग्रह करती है।

ISM 2.0 और पूंजी निवेश

- रिपोर्ट ISM के दूसरे चरण के लिए **10 वर्षों में \$45-60 billion** के सरकारी capital expenditure का अनुमान लगाती है। हालांकि यह राशि उन projects पर खर्च होनी चाहिए जहां जोखिम कम हो और investors को returns की "bankability" सुनिश्चित हो।
- इसका अर्थ है कि focus **frontier chips** (जिनके transistors सबसे छोटे — 3 से 7 nanometres होते हैं) से हटाकर "**mature, advanced—strategic relevance के अनुरूप—तथा compound nodes**" की ओर करना होगा।
- रिपोर्ट **packaging** को — जो chipmaking की अंतिम steps में से एक है और fabrication से कम खर्चीली और जटिल है — "core production pillar, न कि downstream activity" के रूप में पहचानती है।

रणनीतिक साझेदार


- रिपोर्ट चीन को chipmaking में adversary के रूप में इंगित करती है। **Priority partners** में **अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ और दक्षिण कोरिया** को शामिल किया गया है — critical tools, equipment servicing और lifecycle support के लिए तथा India के market scale, talent base और packaging capacity का लाभ उठाने के लिए।

महत्व

- यह रिपोर्ट ISM 2.0 की संभावित रूपरेखा को समझने में महत्वपूर्ण है। यह "selective depth, capital efficiency और system-level differentiation" की वकालत करती है — न कि पूरे global manufacturing spectrum को replicate करने का प्रयास। IT Secretary S. Krishnan ने रिपोर्ट को "structured, actionable framework" बताते हुए कहा कि "भारत अपनी semiconductor महत्वाकांक्षा को औद्योगिक और रणनीतिक वास्तविकता में बदलने के लिए अच्छी स्थिति में है।"

स्रोत: NITI Aayog Frontier Tech Hub | The Hindu | India Semiconductor Mission

4. CBSE की मूल्यांकन प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता: On-Screen Marking विवाद और सुधार की राह



Committed To Excellence

THE HINDU

Current Affairs Analysis

03 June 2026

The Hindu Page No- 13


Can CBSE's marking system be reformed for transparency and credibility?

Portal glitches, blurred scans, and evaluation anomalies exposed weaknesses in the rollout of the OSM system. Robust SOPs, secure digital infrastructure, and free access to answer scripts can help restore accountability and public trust in the evaluation process

Rajeev Kumar

The Central Board of Secondary Education (CBSE), responding to long-standing demands for greater transparency in evaluation, introduced the on-screen marking (OSM) system to standardise answer-script assessment through digital technology. Under this framework, answer books are scanned into secure digital files and evaluated online through a cyber-secure platform enabling digital monitoring, random allocation of scripts, centralised moderation, and automated verification checks.

The initiative sought to improve transparency, accuracy, confidentiality, and uniformity in marking. However, it soon faced controversies over server failures, portal glitches, blurred or



CBSE की मूल्यांकन प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता: On-Screen Marking विवाद और सुधार की राह

डिजिटल OSM प्रणाली में तकनीकी खामियां, धुंधले scan और असंगत marking ने उठाए गंभीर नैतिक सवाल

3 जून, 2026 | शासन एवं नीति | शिक्षा

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की डिजिटल **On-Screen Marking (OSM)** प्रणाली के जल्दबाजी में लागू किए जाने से गंभीर तकनीकी खामियां, धुंधले script scans और असंगत marking patterns सामने आए हैं। इस विवाद ने सार्वजनिक संस्थाओं में **पारदर्शिता और विश्वसनीयता** के मूलभूत सवाल खड़े कर दिए हैं।

पारदर्शिता और विश्वसनीयता क्या हैं?

- **पारदर्शिता** सार्वजनिक प्रशासन में किसी संस्था का वह नैतिक दायित्व है जिसके तहत वह खुले, पूर्वानुमानित और समझ में आने वाले तरीके से काम करे। शिक्षा के संदर्भ में यह छात्र का यह अधिकार है कि वह जान सके कि मूल्यांकनकर्ता ने किस मानदंड, पद्धति और चरणों का पालन करते हुए उसके कार्य का आकलन किया।
- **विश्वसनीयता** वह नैतिक पूंजी है जो कोई संस्था समय के साथ विश्वसनीयता, निष्पक्षता, विशेषज्ञता और निरंतरता के आधार पर अर्जित करती है। जब किसी संस्था की विश्वसनीयता उच्च होती है तो उसके प्रमाण पत्र और मूल्यांकन समाज द्वारा मानव प्रगति के वैध और न्यायपूर्ण मानदंडों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

पारदर्शिता और विश्वसनीयता का महत्व

- **वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत:** खुली और विश्वसनीय मूल्यांकन प्रणाली सुनिश्चित करती है कि विश्वविद्यालय प्रवेश और छात्रवृत्ति जैसे सार्वजनिक पुरस्कार केवल योग्यता के आधार पर मिलें। Class XII के छात्रों के लिए सटीक मूल्यांकन सीधे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालय प्रवेश का निर्णय करता है।
- **प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकना:** सार्वजनिक जांच के तहत काम करने से संस्थाएं मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकतीं। Comprehensive subject marking schemes एक सप्ताह में जारी करने से परीक्षकों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह रोका जा सकता है।
- **नागरिक विश्वास को बढ़ावा:** जब सार्वजनिक संस्थाएं पूर्ण स्पष्टता के साथ काम करती हैं तो सामाजिक सद्भाव बनता है। Scanned answer books मुफ्त में प्रदान करने से सार्वजनिक संदेह और कानूनी विवाद कम होते हैं।
- **संगठनात्मक सुधार:** Digital audit trails और anomaly-detection systems पर्यवेक्षकों को मूल्यांकन त्रुटियों को तुरंत पकड़ने में सक्षम बनाते हैं।

संबंधित नैतिक सिद्धांत

- **Deontological Ethics (Kant):** सार्वजनिक संस्थाओं का छात्रों की rights की रक्षा करने का absolute नैतिक कर्तव्य है। परीक्षा बोर्डों को छात्रों के साथ ends in themselves की तरह व्यवहार करना चाहिए — उन्हें यह सत्यापित करने का अधिकार है कि उनकी scripts पूर्ण, पठनीय और नियमों के अनुसार मूल्यांकित हैं।
- **Utilitarianism (Bentham और Mill):** "सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे अधिक खुशी।" जल्दबाजी में किए गए digital rollouts जो server errors और grading anomalies पैदा करते हैं, लाखों छात्रों और परिवारों को व्यापक कष्ट देकर इस सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं।
- **Rawlsian Justice (Veil of Ignorance):** संस्थागत नियम सबसे कमजोर stakeholders की रक्षा के लिए डिज़ाइन होने चाहिए। Digitised answer scripts देखने के लिए उच्च शुल्क वसूलना कम आय वाले परिवारों के खिलाफ भेदभाव करता है।

पारदर्शिता और विश्वसनीयता की चुनौतियां

- **अपर्याप्त प्रशिक्षण के साथ जल्दबाजी में systems का रोलआउट:** OSM rollout में pilot testing के बिना तेजी से deployment से गंभीर marking errors, असमान step-grading और unchecked answers की समस्या आई।
- **सार्वजनिक records तक पहुंच का व्यावसायीकरण:** नागरिकों को उनके अपने records देखने के लिए उच्च शुल्क देना एक financial barrier बनाता है जो accountability को रोकता है।
- **कमजोर Infrastructure:** Poor-quality scanning equipment ने धुंधली और अधूरी digital files बनाई जिससे fair grading असंभव हो गई।
- **बाहरी Quality Audits का अभाव:** Real-time independent moderation की अनुपस्थिति ने arbitrary marking variations को बिना पकड़े पार होने दिया।

आगे की राह

- **Digital Answer Scripts तक मुफ्त और खुली पहुंच:** सभी छात्रों को परीक्षा के दो सप्ताह के भीतर secure online portals के माध्यम से encrypted, scanned answer copies निःशुल्क प्रदान करें।
- **व्यापक Pre-Board Stress Testing:** Local school exams के दौरान digital servers पर full-scale mock simulations और load testing अनिवार्य करें।
- **मानकीकृत Step-Marking Guidelines:** परीक्षकों की व्यक्तिपरकता समाप्त करने के लिए परीक्षा के एक सप्ताह के भीतर subject-wise grading keys और acceptable alternative solutions ऑनलाइन जारी करें।
- **Automated Digital Audit Controls:** Grading consistency सुनिश्चित करने के लिए evaluation software में AI-driven totaling checks, real-time online moderation और anomaly-detection trackers embed करें।
- **Staff के लिए Ethics और Digital Training:** सभी evaluators, scanning operators और system managers को scripts review करने से पहले digital handling और ethical grading practices में formal training पूरी करनी हो।

निष्कर्ष

मूल्यांकन ढांचा शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का नैतिक आधार है। On-Screen Marking जैसे digital platforms पर स्थानांतरण आधुनिकीकरण के मूल्यवान अवसर प्रदान करता है — लेकिन उचित infrastructure या staff training के बिना जल्दबाजी में rollout सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करने और व्यापक छात्र समुदाय के साथ प्रणालीगत अन्याय का जोखिम उठाता है। संस्थागत विश्वसनीयता एक बार खोने के बाद पुनर्निर्माण में दशकों लग जाते हैं।

स्रोत: The Hindu | CBSE | शिक्षा मंत्रालय

5. RudraM-II मिसाइल का सफल परीक्षण: भारत की precision strike क्षमता में नया अध्याय



Committed To Excellence

THE HINDU

Current Affairs Analysis

03 June 2026

The Hindu Page No- 13



RudraM-II मिसाइल का सफल परीक्षण: भारत की precision strike क्षमता में नया अध्याय

Indigenous RudraM-II missile clears flight trials

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Defence Research and Development Organisation (DRDO) and the Indian Air Force (IAF) have successfully conducted flight-tests of the indigenous RudraM-II air-to-surface missile, marking a significant milestone in India's efforts to

DRDO और IAF ने मिलकर किया स्वदेशी air-to-surface मिसाइल का सफल flight-test — ITR चांदीपुर ने की tracking

3 जून, 2026 | रक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी | DRDO

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय वायु सेना (IAF) ने स्वदेशी **RudraM-II air-to-surface मिसाइल** का सफलतापूर्वक flight-test किया है। यह भारत की precision strike क्षमताओं को मजबूत करने और रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

परीक्षण का विवरण

- रक्षा मंत्रालय के अनुसार मिसाइल को एक **airborne platform** से **extreme release conditions** के तहत test-fire किया गया। परीक्षण सभी critical subsystems और flight parameters के प्रदर्शन को validate करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे।
- Integrated Test Range (ITR), चांदीपुर** द्वारा तैनात tracking और monitoring instruments के नेटवर्क के माध्यम से captured data ने मिसाइल के प्रदर्शन और परीक्षणों की सफलता की पुष्टि की।

RudraM-II का महत्व

- Precision Strike Capability:** RudraM-II एक स्वदेशी air-to-surface मिसाइल है जो वायु सेना को जमीनी लक्ष्यों पर सटीक प्रहार करने की क्षमता देती है। यह दुश्मन के radar systems, communication centers और अन्य strategic targets को neutralize करने में सक्षम है।
- Atmanirbhar Bharat को बल:** DRDO का यह सफल परीक्षण रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ठोस कदम है। स्वदेशी precision strike weapons की उपलब्धता भारत को import dependence से मुक्त करती है और strategic autonomy को मजबूत करती है।
- IAF की operational क्षमता में वृद्धि:** RudraM series की मिसाइलें IAF को Anti-Radiation Missile (ARM) क्षमता प्रदान करती हैं — जो enemy air defense systems को suppress करने के लिए अनिवार्य है।
- ITR चांदीपुर की भूमिका:** ओडिशा में स्थित Integrated Test Range भारत के मिसाइल परीक्षण का प्रमुख केंद्र है। इसकी sophisticated tracking infrastructure ने परीक्षण के सभी parameters की real-time निगरानी सुनिश्चित की।

RudraM Series का संदर्भ

- RudraM series DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी anti-radiation missiles की श्रृंखला है।

- RudraM-I का भी पहले सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है।
- RudraM-II इस series का अधिक उन्नत संस्करण है जो extreme conditions में भी सटीक प्रदर्शन करने में सक्षम है।

महत्व

- वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में — जहां भारत को उत्तर और पश्चिम दोनों सीमाओं पर चुनौतियों का सामना है — स्वदेशी precision strike weapons का विकास रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- RudraM-II की सफलता भारत के Defence Technology Ecosystem की परिपक्वता का प्रमाण है और यह संदेश देती है कि भारत अब केवल defence importer नहीं बल्कि एक capable defence manufacturer बन रहा है।

स्रोत: रक्षा मंत्रालय | DRDO | IAF | ITR चांदीपुर

Current Affairs Based Daily Current Affairs Quiz

Q1. MSV Climate Research रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह रिपोर्ट Indian Institute of Science, बंगलुरु को नोडल संस्था के रूप में तैयार की गई है।
2. MSV exercise पहली बार जलवायु अनुसंधान, पारिस्थितिकी और खगोल विज्ञान तक विस्तारित की गई है।
3. रिपोर्ट ने GeM portal को वैज्ञानिक संस्थाओं के लिए आदर्श procurement mechanism बताया है।
4. रिपोर्ट ने एक indigenous Earth System Model "first principles" से बनाने की सिफारिश की है।

कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

व्याख्या: कथन 1 सही है — IISc बंगलुरु नोडल संस्था है। कथन 2 सही है — पहली बार climate research, ecology और astronomy तक विस्तारित। कथन 3 गलत है — रिपोर्ट में GeM portal को stumbling block बताया गया है क्योंकि vendors अक्सर customized equipment specifications पूरी नहीं कर पाते। यह Atmanirbhar नीति के साथ "awkward" स्थिति बताई गई है। कथन 4 सही है — indigenous Earth System Model की सिफारिश।

Q2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. MSV रिपोर्ट के अनुसार uncalibrated imported equipment से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में गलत डेटा रिपोर्ट किया जा रहा है।
2. रिपोर्ट नवीकरणीय ऊर्जा को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए इसके दुष्प्रभावों की चेतावनी देती है।
3. Finance Ministry ने June 2025 में sub-standard materials की शिकायतों के बाद GeM के कुछ नियमों में ढील दी।
4. MSV रिपोर्ट PSA कार्यालय को सौंपी गई है जो Professor Ajay K. Sood की अगुवाई में है।

कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

व्याख्या: कथन 1 सही है — uncalibrated equipment से गलत डेटा। कथन 2 गलत है — रिपोर्ट का दृष्टिकोण **सतर्कतापूर्ण है, संशयपूर्ण नहीं।** वैज्ञानिक नवीकरणीय ऊर्जा को अस्वीकार नहीं करते बल्कि "uncontrolled" growth के दीर्घकालिक अध्ययन की मांग करते हैं। कथन 3 सही है — Finance Ministry ने June 2025 में ढील दी। कथन 4 सही है — PSA कार्यालय और Professor Ajay K. Sood।

Q3. CBSE की OSM प्रणाली और पारदर्शिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. Rawlsian Justice के अनुसार digitised answer scripts देखने के लिए उच्च शुल्क वसूलना Veil of Ignorance सिद्धांत के विरुद्ध है।
2. Deontological Ethics के तहत public institutions का students को ends in themselves मानने का नैतिक दायित्व है।
3. Utilitarian दृष्टिकोण के अनुसार जल्दबाजी में digital rollout "greatest happiness for the greatest number" सुनिश्चित करता है।
4. OSM प्रणाली की खामियों में धुंधले script scans और असंगत marking patterns शामिल हैं।

कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

व्याख्या: कथन 1 सही है — Rawlsian Justice में vulnerable stakeholders की रक्षा अनिवार्य है — उच्च शुल्क कम आय परिवारों के विरुद्ध भेदभाव है। कथन 2 सही है — Kantian Deontological Ethics में students को ends in themselves माना जाना अनिवार्य है। कथन 3 गलत है — बिल्कुल उल्टा। Utilitarian सिद्धांत कहता है कि जल्दबाजी में rollout लाखों छात्रों को distress देकर इस सिद्धांत का **उल्लंघन** करता है। कथन 4 सही है — OSM की इन्हीं खामियों ने विवाद जन्म दिया।

Q4. RudraM-II के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. RudraM-II एक surface-to-air मिसाइल है जिसे DRDO और IAF ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।
2. RudraM-II का flight-test Integrated Test Range (ITR), चांदीपुर से किया गया।
3. मिसाइल को airborne platform से extreme release conditions में test-fire किया गया।
4. RudraM series Anti-Radiation Missile (ARM) क्षमता प्रदान करती है।

कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

व्याख्या: कथन 1 गलत है — RudraM-II एक **air-to-surface** मिसाइल है, surface-to-air नहीं — category का classic twist। कथन 2 सही है — ITR चांदीपुर ने tracking की। कथन 3 सही है — airborne platform, extreme release conditions। कथन 4 सही है — ARM क्षमता enemy air defense systems को suppress करती है।

Q5. भूमि पूलिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गुजरात में TP Scheme को Gujarat Town Planning and Urban Development Act, 1976 के तहत औपचारिक किया गया।

- TP Scheme में भूखंड मालिक 25-40% भूमि बुनियादी ढांचे के लिए योगदान करते हैं और 60-75% serviced plots के रूप में वापस पाते हैं।
- गुवाहाटी में TP Scheme में private landowners से 35-45% भूमि योगदान की मांग की गई।
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 ने भूमि अधिग्रहण की वित्तीय जटिलताओं को बढ़ाया।

कितने कथन सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- केवल तीन
- सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

व्याख्या: कथन 1 सही है — Gujarat Town Planning and Urban Development Act, 1976। कथन 2 सही है — 25-40% योगदान, 60-75% वापसी। कथन 3 गलत है — गुवाहाटी में योजना को अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए केवल **12-15%** भूमि योगदान मांगा गया — सामान्य 35-45% से बहुत कम। यही Guwahati की key innovation थी। कथन 4 सही है — 2013 Act से वित्तीय दायित्व बढ़े।

Q6. India Semiconductor Mission के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- ISM का corpus ₹76,000 करोड़ है।
- भारत का पहला fab unit 2028 तक गुजरात के धोलेरा में खुलने की उम्मीद है।
- NITI Aayog की रिपोर्ट के अनुसार ISM 2.0 के लिए 10 वर्षों में \$45-60 billion का सरकारी capital expenditure आवश्यक है।
- रिपोर्ट में frontier chips (3-7 nanometre) के निर्माण पर अधिकतम ध्यान देने की सिफारिश की गई है।

कितने कथन सही हैं?

- केवल एक
- केवल दो
- केवल तीन
- सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

व्याख्या: कथन 1 सही है — ₹76,000 करोड़ corpus। कथन 2 सही है — 2028 तक Dholera में पहला fab। कथन 3 सही है — \$45-60 billion, 10 वर्ष। कथन 4 गलत है — रिपोर्ट **frontier chips से focus हटाकर "mature, advanced और compound nodes"** की ओर करने की सिफारिश करती है। Frontier chips में public funds लगाना इसलिए उचित नहीं क्योंकि जोखिम बहुत अधिक है।

Q7. NITI Aayog की semiconductor रिपोर्ट में "priority partners" के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

- अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया
- अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ, ताइवान
- अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया
- अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया

उत्तर: (a)

व्याख्या: रिपोर्ट में **USA, Japan, European Union और South Korea** को priority partners बताया गया है — critical tools, equipment servicing और lifecycle support के लिए। **China को adversary** के रूप में इंगित किया गया है। **Taiwan** का उल्लेख geopolitical risk के संदर्भ में है, priority partner के रूप में नहीं।

Q8. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

राज्य	भूमि पूलिंग से संबंधित तथ्य
1. गुजरात	1,000 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र TP schemes से नियोजित
2. राजस्थान	2016 से statutory provisions में भूमि पूलिंग मान्यता
3. महाराष्ट्र	सफलतापूर्वक statutory provisions को समय पर update किया
4. गुवाहाटी	Digitised land records अभाव के कारण revenue records आधार बनाए

कितने युग्म सही सुमेलित हैं?

- (a) केवल दो
- (b) केवल तीन
- (c) सभी चार
- (d) केवल एक

उत्तर: (b) केवल तीन

व्याख्या: युग्म 1 सही है — गुजरात में 1,000 sq. km। युग्म 2 सही है — राजस्थान में 2016 से statutory provisions। युग्म 3 गलत है — महाराष्ट्र गुजरात के विपरीत अपने statutory provisions को समय पर update करने में विफल रहा। युग्म 4 सही है — गुवाहाटी में revenue records को आधार बनाया।

Q9. CBSE OSM प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय MSV रिपोर्ट में सुझाए गए Way Forward के अनुसार सही नहीं है?

- (a) सभी छात्रों को परीक्षा के दो सप्ताह के भीतर encrypted scanned answer copies निःशुल्क प्रदान करना
- (b) Local school exams के दौरान digital servers पर full-scale mock simulations और load testing अनिवार्य करना
- (c) छात्रों को answer scripts देखने के लिए nominal fee लेकर transparency सुनिश्चित करना
- (d) AI-driven totaling checks और real-time anomaly-detection trackers evaluation software में embed करना

उत्तर: (c)

व्याख्या: (a), (b), और (d) सभी सुझाए गए Way Forward उपाय हैं। (c) गलत है क्योंकि रिपोर्ट "free of charge" access की सिफारिश करती है — किसी भी fee को Rawlsian Justice के विरुद्ध माना गया है जो कम आय परिवारों के लिए financial barrier बनाता है।

Q10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. RudraM-II का परीक्षण extreme release conditions में किया गया जिससे सभी critical subsystems validate हुए।
2. Integrated Test Range (ITR) चांदीपुर महाराष्ट्र में स्थित है।
3. RudraM series का उद्देश्य IAF को Anti-Radiation Missile क्षमता प्रदान करना है जो enemy air defense systems को suppress करती है।
4. MSV रिपोर्ट की तरह RudraM-II का सफल परीक्षण भी "sovereign design capability" के विकास की दिशा में एक कदम है।

कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (c) केवल तीन

व्याख्या: कथन 1 सही है — extreme release conditions में सभी subsystems validate। कथन 2 गलत है — Integrated Test Range (ITR) चांदीपुर ओडिशा में स्थित है, महाराष्ट्र में नहीं — location twist। कथन 3 सही है — ARM क्षमता और enemy air defense suppression। कथन 4 सही है — दोनों Atmanirbhar Bharat और sovereign capability के उदाहरण।

3rd June 2026 – News Article Based Mains Question

Topic 1: Mega Science Vision-2035 और जलवायु उपकरण संकट (GS-3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण)

प्रश्न 1: "भारत ने अपने वैज्ञानिक उपकरण बनाने की क्षमता लगभग खो दी है।" MSV-2035 रिपोर्ट की इस चेतावनी के संदर्भ में Atmanirbhar Bharat और GeM portal की नीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द | 15 अंक | GS-3)

मॉडल संरचना:

- **भूमिका:** IISc की अगुवाई में PSA कार्यालय को सौंपी गई MSV-2035 रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि uncalibrated imported equipment से भारतीय विज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।
- **समस्या का विश्लेषण:** GeM portal की अनिवार्यता — lowest-bidding vendors specifications पूरी नहीं कर सकते। Global tender में bureaucratic delays। June 2025 में Finance Ministry ने ढील दी — लेकिन structural problem बनी रही। नवीकरणीय ऊर्जा के "uncontrolled" growth के दीर्घकालिक जलवायु प्रभाव अज्ञात — जबकि India का 500 GW non-fossil target 2030।
- **Atmanirbhar का विरोधाभास:** Self-reliance का उद्देश्य घरेलू manufacturing बढ़ाना — लेकिन scientific instrument manufacturing की specialized nature को GeM की lowest-bid व्यवस्था accommodate नहीं कर पाती।
- **सुझाव:** Scientific instruments के लिए GeM से exemption या specialized category, Indigenous instrument manufacturing को PLI scheme से जोड़ना, MSV के आठ Mega Projects को mission-mode में लागू करना, indigenous Earth System Model विकास को priority।
- **निष्कर्ष:** Atmanirbhar Bharat का वास्तविक अर्थ केवल procurement नीति नहीं — बल्कि genuine scientific manufacturing capability का निर्माण है।

प्रश्न 2: नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार और जलवायु अनुसंधान की आवश्यकता के बीच संतुलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।

(150 शब्द | 10 अंक | GS-3)

मॉडल संरचना:

- **भूमिका:** India का 500 GW non-fossil target। 2025 में installed capacity का 50% non-fossil। लेकिन large solar और wind plants के जलवायु प्रभाव "poorly understood।"
- **तर्क:** Large-scale solar farms से albedo में बदलाव, local temperature patterns प्रभावित, wind farms से bird mortality और local wind patterns में परिवर्तन।
- **संतुलन की आवश्यकता:** Renewable ≠ automatically climate-neutral। Long-term ecological monitoring अनिवार्य। "Polluter pays" सिद्धांत renewable sector पर भी लागू हो।
- **निष्कर्ष:** Cautionary approach — rejection नहीं।

Topic 2: CBSE OSM और पारदर्शिता (GS-2: शासन / Ethics Paper-IV)

प्रश्न 3: "सार्वजनिक संस्थाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता है।" CBSE की OSM प्रणाली की विफलताओं के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। (250 शब्द | 15 अंक | GS-4/Ethics)

मॉडल संरचना:

- **भूमिका:** CBSE OSM में तकनीकी खामियां, धुंधले scans और असंगत marking ने लाखों छात्रों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लगाया।
- **नैतिक सिद्धांतों से विश्लेषण:**
 - ✓ *Deontological (Kant):* Students ends in themselves — complete, readable, fairly evaluated scripts का अधिकार। OSM failure = Kantian duty का उल्लंघन।
 - ✓ *Utilitarianism (Bentham-Mill):* Hurried rollout ने millions को distress दिया — greatest happiness सिद्धांत का उल्लंघन। True utilitarian value = robust infrastructure।
 - ✓ *Rawlsian Justice:* High fees for script access = कम आय परिवारों के विरुद्ध भेदभाव। Veil of ignorance के पीछे कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं चुनेगा।
- **संस्थागत विफलता के आयाम:** Pilot testing का अभाव, poor scanning hardware, external audit mechanism का अभाव, staff training की कमी।
- **Way Forward:** Free encrypted digital scripts (2 weeks), AI-driven audit controls, pre-board stress testing, mandatory ethics training।
- **निष्कर्ष:** Digital modernization के नाम पर जल्दबाजी distributive justice को कमजोर करती है। Institutional credibility एक बार खोने पर पुनर्निर्माण में दशकों लगते हैं।

प्रश्न 4 (Ethics Case Study): आप एक राज्य शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक हैं। OSM प्रणाली के rollout के बाद पता चलता है कि 15% answer scripts में evaluation errors हैं। ऊपर से दबाव है कि results जल्दी घोषित करें क्योंकि admissions की deadline आ रही है। आप क्या करेंगे? नैतिक सिद्धांतों के आधार पर अपने निर्णय की व्याख्या कीजिए। (250 शब्द | 15 अंक | GS-4)

मॉडल संरचना:

- **नैतिक द्वंद्व:** Administrative pressure (deadline) vs Students' rights (fair evaluation)।
- **Stakeholders:** लाखों छात्र, अभिभावक, universities, बोर्ड की credibility, सरकार।
- **निर्णय और तर्क:**
 - ✓ *क्या नहीं करूंगा:* गलत results जारी नहीं करूंगा — यह 15% छात्रों के साथ घोर अन्याय होगा।
 - ✓ *क्या करूंगा:* पहले — सभी 15% affected scripts की manual re-evaluation का आदेश। दूसरे — सार्वजनिक notification कि results में delay होगी और क्यों — transparency। तीसरे — universities को inform करके admission deadline extend करने का अनुरोध। चौथे — independent technical audit का आदेश।
 - ✓ *Kantian justification:* छात्र end हैं, means नहीं। *Utilitarian:* Short-term delay > lifelong injustice से होने वाला नुकसान। *Rawlsian:* सबसे कमजोर छात्र — जो गलत marks से सबसे अधिक प्रभावित होंगे — की रक्षा।
- **निष्कर्ष:** Institutional integrity administrative convenience से बड़ी होती है।

Topic 3: RudraM-II और रक्षा आत्मनिर्भरता (GS-3: रक्षा, Internal Security)

प्रश्न 5: भारत के स्वदेशी रक्षा अनुसंधान कार्यक्रम की उपलब्धियों और चुनौतियों का परीक्षण करते हुए बताइए कि DRDO किस प्रकार Atmanirbhar Bharat के रक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान दे रहा है। (250 शब्द | 15 अंक | GS-3)

मॉडल संरचना:

- **भूमिका:** RudraM-II का सफल परीक्षण DRDO की बढ़ती क्षमता का प्रमाण। भारत विश्व का सबसे बड़ा arms importer था — अब exporter बनने की राह पर।
- **DRDO की उपलब्धियां:** RudraM series — Anti-Radiation Missile, precision strike। Tejas — indigenous fighter aircraft। Akash — surface-to-air missile। Astra — air-to-air missile। DRDO की इन सफलताओं ने import substitution को बल दिया।
- **चुनौतियां:** Technology transfer की जटिलता, private sector integration अभी limited, DRDO का gestation time लंबा, cutting-edge manufacturing के लिए ecosystem अभी nascent।
- **Institutional reforms:** iDEX (innovations for Defence Excellence), DPP (Defence Procurement Policy), FDI in defence to 74% under automatic route, Defence Corridors in UP और Tamil Nadu।
- **RudraM-II का strategic significance:** ARM capability enemy के radar और SAM systems को neutralize करती है — यह suppression of enemy air defenses (SEAD) का core element है।
- **निष्कर्ष:** DRDO की हर सफलता strategic autonomy को मजबूत करती है। Private-Public partnership और greater accountability से DRDO की efficiency और बढ़ सकती है।

Topic 4: Land Pooling और शहरी बुनियादी ढांचा (GS-2: शासन | GS-3: बुनियादी ढांचा)

प्रश्न 6: "भूमि पूलिंग भूमि अधिग्रहण की संरचनात्मक सीमाओं का एक participatory विकल्प है।" इस कथन की विवेचना करते हुए भारत में Town Planning Schemes की सफलता और विफलता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द | 15 अंक | GS-2/GS-3)

मॉडल संरचना:

- **भूमिका:** LARR Act 2013 के बाद land acquisition महंगा और जटिल। भूमि पूलिंग voluntary, participatory alternative।
- **TP Scheme का mechanism:** 25-40% land contribution, 60-75% serviced plots वापसी। Financial self-sustaining — incremental charges। People-centric approach।
- **सफलता के कारण (गुजरात model):** 100 साल का अनुभव, Gujarat Town Planning Act 1976, 1000+ sq. km नियोजित, strong institutional framework।
- **विफलता के कारण:** महाराष्ट्र — statutory provisions update नहीं। गुवाहाटी — digitized land records का अभाव, clarity का अभाव। राजस्थान — अनुभव की कमी।
- **Success factors:** Clear legislation, adjusted land-contribution (Guwahati में 12-15%), equitable financial models, communication with landowners, digitized records।
- **आगे की राह:** Tamil Nadu, MP, Delhi को Gujarat से सीखकर localized innovation। Central government का 2019 से TP schemes को promotion।
- **निष्कर्ष:** Land pooling एक size fits all solution नहीं — localized innovation और institutional flexibility इसकी सफलता की कुंजी है।

Topic 5: India Semiconductor Mission (GS-3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था)

प्रश्न 7: "भारत में semiconductor manufacturing की आवश्यकता केवल आर्थिक नहीं बल्कि एक strategic compulsion है।" NITI Aayog की रिपोर्ट के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए। (250 शब्द / 15 अंक / GS-3)

मॉडल संरचना:

- **भूमिका:** India में अभी एक भी fab नहीं। Semiconductors — consumer gadgets से defence तक। 2028 तक Dholera में पहला fab।
- **Strategic Compulsion:**
 - ✓ *Geopolitical:* Taiwan में कोई घटना = global supply chain disruption। China adversary = import dependency dangerous।
 - ✓ *Defence:* "As many semiconductor parts used in defence systems are produced outside India — national security threat।"
 - ✓ *Economic:* Electronics assembly में भी chips imported।
- **ISM की उपलब्धियां और सीमाएं:** ₹76,000 crore corpus। Fab projects को 50%+ capital subsidies। लेकिन — 4-5 year gestation, 50+ specialized equipment, talent development time-consuming।
- **ISM 2.0 की दिशा:** \$45-60 billion, 10 years। Frontier chips (3-7nm) से focus हटाकर mature nodes की ओर। Packaging — "core production pillar।" Priority partners — US, Japan, EU, South Korea।
- **"Selective depth" strategy:** Capital efficiency और system-level differentiation — न कि full global spectrum replicate करने की कोशिश।
- **निष्कर्ष:** "Sustained, mission-mode commitment over a decade or more" — semiconductor में कोई shortcut नहीं।

Bonus: Integrated/Combo Question

प्रश्न 8: "Atmanirbhar Bharat की सफलता वैज्ञानिक instrument manufacturing, semiconductor fabrication और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों में तभी संभव है जब नीति, संस्थान और निवेश एक साझा दृष्टि से काम करें।" उपर्युक्त कथन की विवेचना कीजिए। (250 शब्द | 15 अंक | GS-3)

मॉडल संरचना:

- **भूमिका:** तीन क्षेत्रों में India की वर्तमान स्थिति — Scientific instruments: import dependent; Semiconductors: zero fabs; Defence: DRDO की growing but incomplete ecosystem।
- **नीति की भूमिका:** ISM ₹76,000 crore। GeM की समस्या — scientific procurement में एक size fits all नहीं। DRDO reform — iDEX, private sector।
- **संस्थागत आवश्यकता:** IISc जैसे institutions को MSV mega projects में नेतृत्व। Semiconductor talent pipeline — universities से fabs तक। ITR Chandipur जैसे testing infrastructure का विस्तार।
- **निवेश की दिशा:** ISM 2.0 — \$45-60 billion, bankable projects। Packaging as core pillar। DRDO में R&D expenditure वृद्धि।
- **तीनों का interconnection:** Semiconductor chips → Defence systems में use। Scientific instruments → Climate research → Policy decisions → Renewable energy planning। सभी एक-दूसरे से जुड़े।
- **निष्कर्ष:** Atmanirbhar Bharat एक integrated vision है — fragmented policy से नहीं बल्कि convergent strategy से साकार होगा।

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन बैच 2026-27

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था

- Daily Revision Test
- साप्ताहिक करेंट मैगजीन
- मेंटर की गाइडेंस
- डाउट क्लीयरिंग सेशंस
- व्यक्तिगत गाइडेंस की सुविधा

कक्षाएँ आरंभ

5 जून सुबह 8:30 बजे

3 दिन की निःशुल्क कार्यशाला

JOIN NOW

Visit: www.gsworldias.in | www.courses.gsworldias.in

9682984000/7905693289

RAMESHWAR SIR

UPPCS 2024 FINAL SELECTION

“SDM बनकर सिर्फ कुर्सी नहीं मिलती, लोगों की उम्मीदों की जिम्मेदारी मिलती है!”



ABHAY PRATAP SINGH
RANK 3 (SDM)



ANAMIKA MISHRA
RANK 4 (SDM)



POOJA TIWARI
RANK 7 (SDM)



ANURAG PANDEY
RANK 8 (SDM)



SHWETA DWIVEDI
RANK 26 (SDM)

Heartiest
Congratulations
to all successful candidates



Niraj Singh
(MD GS World IAS PCS)

Call – 9682984000 / 7905693289 | Download – GS World Learning App | offline- “स्टेनली रोड, निकट ट्रैफिक चौराहा, प्रयागराज”

FOR PDF DOWNLOAD GS WORLD LEARNING APP